तक इस नियम और कानून को ज्यादा सख्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है स्वास्थ्य मंत्रालय में जो कि कानून के खिलाफ है या नियम के बाहर है तो मैं अवश्य की इस संबंध में अपने साथी से चर्चा करूंगा।

श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिंदे : मान्यवर, सम्माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने कोई कानून बनाया है, लेकिन जब फिल्म बनती है, वह चाहे "हाथी मेरे साथी" हो या और कोई सर्कस की फिल्म हो, तो उसमें एक्चुअल एनीमल का कान हो या उसका पैर हो, वह काटते हैं या खाली ट्रिक कर के फिल्म में बताते हैं, इस संबंध में मंत्री जी को जानकारी है क्या? दूसरी बात मैं यह पूछना चाहूंगा कि पूर्व एनवायरनमेंट मिनिस्टर श्रीमती मेनका गांधी जी ने ब्राडकॉस्टिंग मिनिस्टर को एक चिट्ठी लिखी थी कि यह-यह कानून में सुधार होने चाहिए और उस चिट्ठी का भी अंतर्भाव क्या यह जो नया कानून बनाया है, उसमें लिया गया है?

श्री कमल नाथ : सर, जिन जानवरों को फिल्मों में दिखाया जाएगा, उसकी गाइडलाइंस बनी हुई हैं और यह आई. एंड बी. मिनिस्ट्री को भेजी गयी थीं। सर, यह किसी ट्रिक फोटोग्राफी से कर लेते हैं, इसको मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि इस विषय में मेरी भी कोई एक्सपर्टीज नहीं हैं कि फिल्म कैसे ली जाती हैं, लेकिन अगर ऐसी कोई बात माननीय सदस्य के ध्यान में है कि जहां ट्रिक फोटोग्राफी से फिल्म ली जाती है या कानून का उल्लंघन हो रहा है तो, वह मेरी जानकारी में जरूर लाएं। सर, जहां तक यह इश्यू था, यहां हमने एक टीम भेजी थी...(व्यवधान)...

श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिंदे : मान्यवर, अगर यह ज्वाइंट फोटोग्राफी से ली जाती है, तब तो उल्टे यह अच्छा है क्योंकि उसमें जानवरों को नुकसान नहीं होता है। मैं तो यह कह रहा हूं।

श्री कमल नाथ : सर, माननीय सदस्य की यह बात सही है और ऐसा हो सकता है, पर उसकी जो गाइडलाइंस हैं, वह बहुत इलोबोरेट हैं। वह मैं माननीय सदस्य को भेज दूंगा और उनका इस बारे में कोई सुझाव हो तो वह मुझे अवश्य दें।

श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिंदे : सर, मेनका गांधी जी ने जो चिट्ठी लिखी थी और उन्होंने जो सुझाव दिए थे, क्या उनको भी इन गाइडलाइंस में स्वीकार कर लिया गया है या नहीं?

श्री कमल नाथ : सर, स्वीकार करने या नहीं करने का प्रश्न नहीं है। यह तो कानून है, कानून के अंतर्गत नोटिफिकेशन है, रूल्स बनाए गए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी आई. एंड बी. मिनिस्ट्री कोई गैर-कानूनी या नियम के बाहर काम नहीं कर रही है।

MB, CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

World Bank's offer to Control Blindness

*242. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has 'been darwn to a news item published in the Hindustan Times dated 30.1.94 captioned "Union Health Minister turns blind eye" by nearly blowing off the reported offer of the World Bank of Rs. .554 crores for blindness control project which aimed at controlling blindness due to Cataract in 81 per cent cases in

the country concerning six million blind people in India;

(b) whether it is a fact that the Finance Ministry as reported "feels exasperated by the 'unexplained' delay on the part of the Ministry of Health to start negotiations with the World Bank for this last offer" which took over a year and a half to take shape; and

(c) if so, full details thereof indicating as to who is responsible for jeopardising this ambitious project;

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI B. SHANKARANAND): (a) No, Sir. But a misleading news item appeared in the Times of India dated January 30 1994.

(b) No, Sir.
(c) Does not arise.

Resettlement of villagers in Kendrapaja District, Orissa

*246. SHRI PRAVAT KUMAR SAMANTARAY: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the in habitants of villages Satabhaya and Kahnupur under Kedrapara District (Orissa) have submitted a Memoran dum to the Governor of Orissa on his recent visit to the affected area due to coastal erosion;

(b) whether Orissa Government has requested his Ministry according clearance to the resettlement of 393 families of above villages;

(c) what is the total land required for the resettlement of these families as per request of Government of Orissa and what is the total land offered by Government of Orissa in lieu of the proposed land for settlement for afforestation;

(d) whether the land in question for resettlement is adjacent to agricultural fields and there is no exis-

tence of any tree therein except weeds; and

(e) what is Government of India's reaction to this proposal in view of rapid sea erosion at Satabhaya and Kahnupur?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHR KAMAL NATH) : (a) As per the information received from the State Government of Orissa, villagers of Satabhaya and Kahnupur have-submitted a represen-tation to the Governor of Orissa during his recent visit to the area.

(b) and (c) Orissa State Government have sent a proposal for diversion of 532.97 ha. of forest land under the Forest (Conservation) Act, 1980 for rehabilitation of 395 families of Satabhaya and Kahnupur villages in District Cuttack. The State Government has identified 654.066 ha. of non-forest land for raising compensatory afforestation in lieu of the for-est land to be diverted for rehabilitation purposes in the present case.

(d) The entire area proposed for diversion comes under Mangrove tco-system and forfs pert of Bhitar-kanika Wildlife Sanctuary.

(e) After detailed examination of the proposal and site inspection of the forest area involved, the State Government have been requested to send a revised proposal for resettlement of these villagers.

Construction of Railway Station in Ashok Vihar, Delhi

*247. DR. NAUNIHAL SINGH: Win the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether there was a provision to construct a railway station in Ashok Vihar, Delhi to meet the re-quirement of a large number of people residing in Ashok Vihar, Shall